ग्रामसभा तय करेगी किस योजना में खर्च हो राशि

रांची : जिला खनिज फाउंडेशन नीति को लेकर संभावनाओं व चुनौतियों पर शुक्रवार को सेंटर फॉर साइंस एंड इंवायरनमेंट की ओर से होटल लीलैक में कार्यशाला हुई। प्रदेश खनन व भूगर्भ विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार सतपथी ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन से आई राशि किस योजना में खर्च होनी है, यह ग्रामसभा तय करेगी। अर्थशास्त्री रमेश शरण ने कहा कि खनन कार्य सीधे तौर पर आम जनता के हित में होनी चाहिए। खनन से प्रभावित लोगों के हितों के लिए राशि खर्च होनी चाहिए।

संबोधित करतीं सुनीता नारायण।

एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक रमेश शर्मा ने कहा कि जिला खनन फाउंडेशन नीति में आनेवाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संपदाओं को बचाने की कवायद कम दिखती है। सामाजिक स्वीकृति पर इस नीति के संबंध में कम दिखाई पड़ती है। वनाधिकार कानून में गौण खनिजों के लिए ग्राम सभा को अधिकार देने का प्रावधान है। सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा कि समता जजमेंट में सरकार को जनता को 20 प्रतिशत शेयर देने की बात कही गई है। जिला खनन फाउंडेशन में जो राशि आएगी, उसका उपयोग कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा यह ध्यान रखना होगा कि स्थानीय जरूरत क्या है। सीएसई के उपमहानिदेशक चंद्रभूषण ने कहा कि सही उत्खनन के लिए वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए। उमेश नजीर और मिथिलेश झांगी ने सवाल किए और नीति पर संदेह भी व्यक्त किया। मौके पर पत्रकार सोनाली दास, दयामनी बारला, गोपीनाथ घोष, श्रीप्रकाश, फिलीप कुजूर, आलोका सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।